भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1174
बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940 (शक)

सतत विकास लक्ष्य भारतीय सूचकांक-आधार
रेखा रिपोर्ट

1174. श्री कनवर दीप सिंहः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार की समस्या और विकट हो गई है और क्या नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य (एस॰डी॰जी॰) भारतीय सूचकांक-आधार रेखा रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, और क्या 19-59 वर्ष की कार्यशील आयु-वर्ग में प्रति 1000 में 64 व्यक्ति बेरोजगार प्रतीत होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्ण और उत्पादक रोजगार और आर्थिक विकास की बात करने वाले सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स: बेसलाइन रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रति 1000 व्यक्तियों पर औसत बेरोजगारी की गणना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 63.5 (64 के लगभग) के रूप में आंकी गई थी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) पर एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) विकसित किया है, जिसमें उनकी सावधिकता और आंकड़ा स्रोत मंत्रालयों / विभागों के साथ राष्ट्रीय संकेतक शामिल हैं। ये संकेतक संबंधित एसडीजी को कार्यान्वित करने वाले विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी और ट्रैकिंग करने में मदद करेंगे।

इस संबंध में, सरकार ने नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सदस्यों के साथ मिलकर सीएसआई एवं सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (एमओएसपीआई) की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) का गठन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) पर राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क की सावधिक समीक्षा और परिष्करन करेगा, जिसमें उनकी सावधिकता और आंकड़ा स्रोत मंत्रालयों / विभागों के राष्ट्रीय संकेतक शामिल हों। ये संकेतक राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) की प्रगति की निगरानी और ट्रैकिंग करने में मदद करेंगे।

*****